>

Title: Need to promote Ayurveda in the country.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय महोदया, आरोग्य मेला, प्रत्येक वर्ष भारत के विभिन्न शहरों में लगता था जिससे आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार होता था। वह क्यों बंद कर दिया गया? इस मद के लिए सरकार ने 290 करोड़ रूपये स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष विभाग को दिया था जिसे मंत्रालय ने फिर से लौटा दिया है। फंड की कमी होने की वजह से आयुर्वेदिक चिकित्सक इलाज नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट का केवल 2.5 प्रतिशत, आयुष विभाग को दिया गया है इससे आयुर्वेद का भला होने वाला नहीं है। इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है।

पीएससीआई मेडीसिन में 28 टेक्नीकल पद रिक्त पड़े हैं। इसकी रिक्तियां भरे जाने की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सकों के 30 पद रिक्त पड़े हैं। आयुष में सलाहकार(आयुर्वेद) के पद रिक्त पड़े हुए हैं। आयुष विभाग जागरूकता अभियान विज्ञापन को भी बंद कर दिया गया है। मिसीसिपी विश्व विद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का एक नामी-गिरामी विश्वविद्यालय है। वहां पर आयुर्वेद विभाग है जिसने भारत के साथ एक समझौता किया था कि हम लोग मिल कर भारत में आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार तथा रिसर्च भी करेंगे लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समझौते को तोड़ दिया गया है।

आयुर्वेद की सारी दवाइयां पेड़-पौधे, जड़ी-बूटी एवं फूल-पत्ती से मिलते हैं लेकिन अभी जंगल कट रहे हैं। हिमालय के जंगल कट रहे हैं। जहां पर, आयुर्वेद की बहुत-सी जड़ी-बूटियां हैं। पूरी दुनिया में नाम है। इसलिए जड़ी-बूटियों के पौधों को बढ़वा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

भारत से निकला हुआ आयुर्वेद आज मॉरिशस की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति है। इसलिए इसको भारत में भी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित किए जाने की जरूरत है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि आज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री पन्ना लाल पुनिया,

श्री कमल किशोर 'कमांडो' और

श्री देवजी एम. पटेल शून्य प्रहर में श्री कौशलेन्द्र कुमार जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करते हैं।